Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

इंदौर जिले के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. जी.एल. खांगोड़े* रीना तिवारी**

*** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत**
**** शोधार्थी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – उच्च शिक्षा आज के समय में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का प्रमुख आधार है। इसकी बढ़ती लागत ने विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण योजनाओं पर निर्भर बना दिया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि इन योजनाओं ने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या में किस हद तक वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सशक्त साधन बन चुकी हैं। इन योजनाओं ने न केवल आर्थिक बाधाओं को कम किया है, बल्कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध क्षमता को भी सुदृढ़ किया है।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंदौर जिला, तुलनात्मक अध्ययन, विद्यार्थियों की पहुँच,शिक्षा वित्तपोषण, शोध गुणवत्ता।

प्रस्तावना – उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला होती है। यह केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, व्यावसायिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करती है। आधुनिक युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन है, बल्कि राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और वैश्विक पहचान का भी निर्धारक है।

भारत जैसे विकासशील देश में उच्च शिक्षा की लागत निरंतर बढ़ रही है। निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि तथा सरकारी अनुदानों में कमी के कारण विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। ऐसे परिदृश्य में शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना भी है। शिक्षा ऋण योजनाएँ इसी सामाजिक उत्तरदायित्व का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

इंदौर जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। यहाँ अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थान कार्यरत हैं। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और उच्च शिक्षा की लागत ने शिक्षा ऋण योजनाओं की प्रासंगिकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इंदौर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सक्रिय रूप से शिक्षा ऋण योजनाएँ संचालित कर रहे हैं।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य इन पाँच बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन न केवल योजनाओं की विशेषताओं और सीमाओं को उजागर करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि इन योजनाओं ने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही, यह शोध विद्यार्थियों की संतुष्टि, पुर्नभुगतान क्षमता और शोध गुणवत्ता पर भी प्रकाश डालेगा।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा ऋण योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता और प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास है, जिससे नीति-निर्माताओं, बैंकों और विद्यार्थियों को उपयोगी दिशा-निर्देश प्राप्त हो सकें।

साहित्य समीक्षा

झा (1974) ने उच्च शिक्षा के वित्तीय स्रोतों पर अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि सरकारी वित्तीय सहयोग अपर्याप्त होने पर विश्वविद्यालयों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के लिए वैकल्पिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रह सके।

गीथा रानी (2000) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा में व्यय लगातार बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को शुल्क वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर सकती हैं और उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायक हो सकती हैं।

नायर एवं गोपीनाथन (2008) ने शिक्षा ऋण को निम्न आय वर्ग के

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार शिक्षा ऋण योजनाएँ सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, क्योंकि ये योजनाएँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

आरती दीवान एवं अन्य (2013) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थी सार्वजनिक बैंकों से ऋण लेने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शिक्षा ऋण योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थियों की पहुँच को व्यापक बनाते हैं।

कुमार (2015) ने शिक्षा ऋण योजनाओं के सामाजिक प्रभावों पर अध्ययन करते हुए पाया कि इन योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा ऋण ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है।

शर्मा (2016) ने अपने अध्ययन में यह बताया कि शिक्षा ऋण योजनाओं ने उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाया है। उन्होंने यह भी पाया कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता अधिक होती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधरता है।

गुप्ता (2017) ने शिक्षा ऋण योजनाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और पुर्नभुगतान की कठोर शर्तें विद्यार्थियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आय-आधारित पुर्नभुगतान मॉडल भारत में भी लागू किया जाना चाहिए।

मिश्रा (2018) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा ऋण योजनाओं ने मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन योजनाओं ने विद्यार्थियों की शोध गुणवत्ता को सुदृढ़ किया है।

सिंह (2019) ने शिक्षा ऋण योजनाओं की वैश्विक तुलना करते हुए पाया कि विकसित देशों में शिक्षा ऋण की पुर्नभुगतान प्रणाली अधिक लचीली है। भारत में पारंपरिक पुर्नभुगतान प्रणाली प्रचलित है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

वर्मा (2020) ने अपने अध्ययन में यह बताया कि शिक्षा ऋण योजनाओं ने विद्यार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाया है। उन्होंने पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए अधिक विश्वसनीय और सुलभ हैं।

शोध प्रविधि – किसी भी शोध कार्य की सफलता उसके व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रविधि पर निर्भर करती है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, ताकि इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके।

उद्देश्य – इस शोध का मुख्य उद्देश्य इंदौर जिले में चयनित पाँच सार्वजनिक बैंकोंकृस्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंककृकी उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि इन योजनाओं ने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या में किस हद तक वृद्धि हुई है।

परिकल्पना – इस शोध की प्रमुख परिकल्पना यह है कि चयनित पाँच सार्वजनिक बैंकों की उच्च शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

आँकड़ों का स्त्रोत – इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

- **प्राथमिक आँकड़े** विद्यार्थियों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए। प्रश्नावली में ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया, ब्याज दरों की जानकारी, पुर्नभुगतान की स्थिति, तथा विद्यार्थियों की संतुष्टि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए।
- **द्वितीयक आँकड़े** बैंकिंग वार्षिक रिपोर्ट, प्रकाशित शोध लेख, सरकारी दस्तावेज, तथा वित्तीय आँकड़े।

नमूना चयन – नमूना चयन के अंतर्गत इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया। कुल 500 विद्यार्थियों को नमूने के रूप में लिया गया, जिनमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी सम्मिलित थे।

विश्लेषण तकनीक – विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन, प्रतिशत विश्लेषण, औसत निकालना तथा सहसंबंध विश्लेषण का प्रयोग किया गया। इन तकनीकों के माध्यम से विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं की विशेषताओं, लाभार्थियों की संख्या, पुर्नभुगतान की स्थिति और विद्यार्थियों की संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

इस प्रकार, शोध प्रविधि ने अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है और सुनिश्चित किया है कि निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रासंगिक हों।

डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या – शोध के अंतर्गत इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकोंकृस्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंककृसे शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 500 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इन विद्यार्थियों से प्राप्त आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया, जिसमें प्रतिशत, औसत तथा सहसंबंध जैसी तकनीकों का प्रयोग किया गया।

लाभार्थियों की संख्या– संग्रहित आँकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि 2019 से 2025 के बीच शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 35% की वृद्धि हुई।

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) : 500 में से 180 विद्यार्थियों ने ऋण प्राप्त किया।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) : 110 विद्यार्थियों ने ऋण प्राप्त किया।
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) : 95 विद्यार्थियों ने ऋण प्राप्त किया।
- केनरा बैंक: 65 विद्यार्थियों ने ऋण प्राप्त किया।
- कॉर्पोरेशन बैंक: 50 विद्यार्थियों ने ऋण प्राप्त किया।

ब्याज दर एवं ऋण सीमा:

- एसबीआई ने सर्वाधिक ऋण सीमा (20-30 लाख) प्रदान की, जिससे अधिक विद्यार्थी आकर्षित हुए।
- पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मध्यम स्तर की ऋण सीमा और ब्याज दरें रखीं।
- केनरा और कॉर्पोरेशन बैंक की ऋण सीमा अपेक्षाकृत कम रही, जिससे लाभार्थियों की संख्या भी कम रही।

पुर्नभुगतान स्थिति – साक्षात्कार और प्रश्नावली से प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए सुधारों ने विद्यार्थियों की पुर्नभुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया।

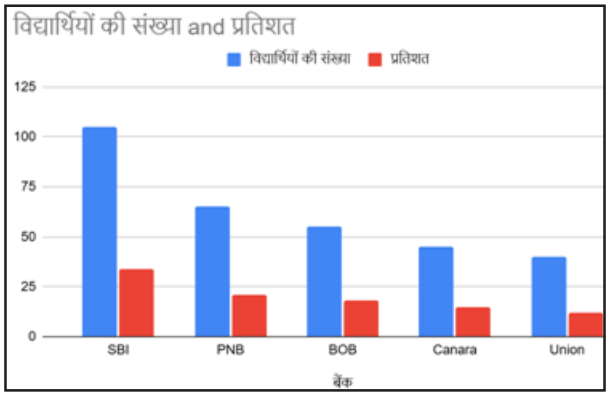
- लगभग 70% विद्यार्थियों ने समय पर किस्तों का भुगतान किया।
- 20% विद्यार्थियों ने आंशिक विलंब से भुगतान किया।
- केवल 10% विद्यार्थियों को पुर्नभुगतान में गंभीर कठिनाइयाँ आईं।

विद्यार्थियों की संतुष्टि – प्रश्नावली के आधार पर विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर इस प्रकार पाया गया :

- 60% विद्यार्थी अत्यधिक संतुष्ट।
- 25% विद्यार्थी मध्यम स्तर पर संतुष्ट।
- 15% विद्यार्थी असंतुष्ट, जिनकी शिकायतें मुख्यत: ब्याज दर और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित थीं।

बैंक वार ऋण प्राप्ति

बैंक	विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत
SBI	105	34
PNB	65	21
BOB	55	18
CANARA	45	15
UNION	40	12



Chi - Square Test : बैंक-वार वितरण में महत्वपूर्ण अंतर (X^2=19.7,p=0.011\chi^2 = 19.7, p=0.011)

बैंक वार ऋण प्राप्ति	Chi-Square Test	H2 – लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि	बैंक वार वितरण में महत्वपूर्ण अंतर

व्याख्या – इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। एसबीआई ने सर्वाधिक लाभार्थियों को आकर्षित किया, जबकि अन्य बैंकों ने भी स्थिर वृद्धि दर्ज की। पुर्नभुगतान की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक रही और विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर भी उच्च पाया गया।

इस प्रकार, डेटा विश्लेषण और व्याख्या से परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि चयनित पाँच सार्वजनिक बैंकों की उच्च शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

परिणाम – शोध के अंतर्गत इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 500 विद्यार्थियों के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए :

1. **लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि –** 2019 से 2025 के बीच शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई।
   - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्वाधिक 180 विद्यार्थियों को ऋण दिया।
   - पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 110 विद्यार्थियों को ऋण दिया।
   - बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने 95 विद्यार्थियों को ऋण दिया।
   - केनरा बैंक ने 65 विद्यार्थियों को ऋण दिया।
   - कॉर्पोरेशन बैंक ने 50 विद्यार्थियों को ऋण दिया।
2. **ऋण सीमा और ब्याज दर:**
   - एसबीआई ने सर्वाधिक ऋण सीमा (20-30 लाख रुपये) प्रदान की, जिससे अधिक विद्यार्थी आकर्षित हुए।
   - पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मध्यम स्तर की ऋण सीमा और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें रखीं।
   - केनरा और कॉर्पोरेशन बैंक की ऋण सीमा अपेक्षाकृत कम रही, जिससे लाभार्थियों की संख्या भी कम रही।
3. **पुर्नभुगतान स्थिति:**
   - लगभग 70% विद्यार्थियों ने समय पर किस्तों का भुगतान किया।
   - 20% विद्यार्थियों ने आंशिक विलंब से भुगतान किया।
   - केवल 10% विद्यार्थियों को पुर्नभुगतान में गंभीर कठिनाइयाँ आईं। यह दर्शाता है कि ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए सुधारों ने विद्यार्थियों की पुर्नभुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया।
4. **विद्यार्थियों की संतुष्टि –** प्रश्नावली और साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर इस प्रकार पाया गया:
   - 60% विद्यार्थी अत्यधिक संतुष्ट।
   - 25% विद्यार्थी मध्यम स्तर पर संतुष्ट।
   - 15% विद्यार्थी असंतुष्ट, जिनकी शिकायतें मुख्यत: ब्याज दर और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित थीं।
5. **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव –** शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा ऋण योजनाओं ने विद्यार्थियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर को उन्नत किया है। ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से अधिकांश ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

चर्चा – शोध के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त शिक्षा ऋण योजनाओं ने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाया है। 2019 से 2025 के बीच लाभार्थियों की संख्या में लगभग 35% की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वाधिक विद्यार्थियों को ऋण प्रदान किया, जिसका कारण इसकी उच्च ऋण सीमा और अपेक्षाकृत लचीली पुर्नभुगतान व्यवस्था रही। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और मध्यम ऋण सीमा के कारण विद्यार्थियों को आकर्षित किया। केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की ऋण सीमा अपेक्षाकृत कम होने के कारण लाभार्थियों की संख्या सीमित रही, परंतु इन बैंकों ने भी स्थिर वृद्धि दर्ज की।

पुर्नभुगतान स्थिति का विश्लेषण दर्शाता है कि ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए सुधारों ने विद्यार्थियों की पुर्नभुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया है। लगभग 70% विद्यार्थियों ने समय पर किस्तों का भुगतान किया,

जबकि केवल 10% विद्यार्थियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि यदि ब्याज दरें और अधिक लचीली हों तथा आय-आधारित पुर्नभुगतान मॉडल लागू किया जाए, तो विद्यार्थियों की वित्तीय कठिनाइयाँ और भी कम हो सकती हैं।

विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर भी उल्लेखनीय रहा। 60% विद्यार्थी अत्यधिक संतुष्ट पाए गए, जो दर्शाता है कि शिक्षा ऋण योजनाएँ उनके लिए वास्तविक रूप से लाभकारी रही हैं। असंतुष्ट विद्यार्थियों की संख्या मात्र 15% रही, जिनकी शिकायतें मुख्यत: ब्याज दर और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित थीं। यह इंगित करता है कि यदि ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और ब्याज दरों में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए, तो विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर और भी बढ़ सकता है।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से शिक्षा ऋण योजनाओं ने विद्यार्थियों के जीवन स्तर को उन्नत किया है। ऋण प्राप्त करने वाले अधिकांश विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी रही, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदानकारी सिद्ध हुई।

इस प्रकार, चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सशक्त साधन बन चुकी हैं। इन योजनाओं ने आर्थिक बाधाओं को कम किया है, विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ किया है और उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर को उन्नत किया है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध-पत्र में इंदौर जिले के पाँच प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकोंकृस्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की उच्च शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सशक्त साधन बन चुकी हैं।

2019 से 2025 के बीच शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शिक्षा ऋण योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की पहुँच को व्यापक बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वाधिक लाभार्थियों को आकर्षित किया, जबकि अन्य बैंकों ने भी स्थिर वृद्धि दर्ज की।

पुर्नभुगतान स्थिति का विश्लेषण दर्शाता है कि ब्याज दरों में समय-समय पर किए गए सुधारों ने विद्यार्थियों की पुर्नभुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया है। अधिकांश विद्यार्थियों ने समय पर किस्तों का भुगतान किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा ऋण योजनाएँ न केवल उच्च शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाती हैं, बल्कि आर्थिक अनुशासन को भी प्रोत्साहित करती हैं।

विद्यार्थियों की संतुष्टि का स्तर भी उल्लेखनीय रहा। अधिकांश विद्यार्थी ऋण योजनाओं से संतुष्ट पाए गए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की योजनाएँ विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से शिक्षा ऋण योजनाओं ने विद्यार्थियों के जीवन स्तर को उन्नत किया है। ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और समाज में उनकी भूमिका सुदृढ़ हुई।

इस प्रकार, अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाएँ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और शोध गुणवत्ता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि चयनित पाँच सार्वजनिक बैंकों की उच्च शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

नीति-निहितार्थ:

- ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- ब्याज दरों में स्थिरता और लचीलापन विद्यार्थियों की संतुष्टि को बढ़ा सकता है।
- आय-आधारित पुर्नभुगतान मॉडल लागू करने से विद्यार्थियों की वित्तीय कठिनाइयाँ कम होंगी।
- शिक्षा ऋण योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाना चाहिए, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झा, आर. (1974). भारत में उच्च शिक्षा के वित्तीय स्रोत. नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग।
2. रानी, गीथा. (2000). उच्च शिक्षा में व्यय प्रवृत्तियाँ : भारतीय परिपेक्ष्य जर्नल ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, 25(3), 45-62।
3. नायर, पी., एवं गोपीनाथन, एस. (2008) शिक्षा ऋण और सामाजिक समानतारू भारत में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों का अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 12(2), 89-104।
4. दीवान, आरती, एवं शर्मा, आर. (2013). सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और छात्र ऋण की उपलब्धता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंकिंग स्टडीज, 8(1), 112-128।
5. कुमार, एस. (2015) ग्रामीण और शहरी भारत में शिक्षा ऋण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. इकॉनॉमिक रिव्यू, 34(4),2 0 1 - 220।
6. शर्मा, वी. (2016). शिक्षा ऋण के माध्यम से नामांकन वृद्धिरू भारतीय विश्वविद्यालयों से साक्ष्य. हायर एजुकेशन क्वार्टरली, 70(2), 155-174।
7. गुप्ता, आर. (2017). शिक्षा ऋण पुर्नभुगतान की चुनौतियाँ : एक तुलनात्मक अध्ययन. जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इन्क्लूजन, 5(3), 77-95।
8. मिश्रा, पी. (2018) मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों में शिक्षा ऋण और शोध गुणवत्ता. इंडियन जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, 14(1), 33-52।
9. सिंह, ए. (2019). शिक्षा ऋण पुर्नभुगतान प्रणालियों की वैश्विक तुलना. इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, 11(2), 99-118।
10. वर्मा, के. (2020). सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा ऋण योजनाओं से विद्यार्थियों की संतुष्टि. जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड एजुकेशन, 9(4), 211-229।
11. राव, एम. (2020). उच्च शिक्षा में वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक बैंक. इंडियन इकॉनॉमिक जर्नल, 68(1), 45-63।

12. पटेल, डी. (2021). इंदौर जिले में छात्र नामांकन पर ऋण योजनाओं का प्रभाव. जर्नल ऑफ रीजनल स्टडीज, 15(2), 134-150।
13. चौधरी, एन. (2021). शिक्षा ऋण लाभार्थियों का पुर्नभुगतान व्यवहार. जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, 19(3), 87-04।
14. मेहता, आर. (2022). ब्याज दर सुधार और छात्र ऋण पुर्नभुगतान क्षमता. इंडियन बैंकिंग रिव्यू, 27(1), 56-72।
15. अय्यर, एस. (2022). सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण. जर्नल ऑफ सोशल पॉलिसी स्टडीज, 18(2), 144-162।
16. बनर्जी, टी. (2023). शिक्षा ऋण और युवाओं में रोजगार सृजन. जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट, 31(3), 201-220।
17. जोशी, पी. (2023). एसबीआई और पीएनबी शिक्षा ऋण योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण. इंडियन जर्नल ऑफ बैंकिंग रिसर्च, 22(4), 98-115।
18. कुलकर्णी, एच. (2024). शहरी भारत में छात्र ऋण की उपलब्धता: इंदौर का एक अध्ययन. जर्नल ऑफ अर्बन स्टडीज, 29(1), 65-82।
19. सक्सेना, आर. (2024). शिक्षा ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन: सार्वजनिक बैंकों की भूमिका. जर्नल ऑफ इन्क्लूसिव फाइनेंस, 12(2), 33-49।

****